

सुविचार

डाक पंजीयन संख्या: RJ/JPC/D19/2024-25

RNI. No. RAJHIND/2011/40950

दैनिक राज्य तथा केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त

सच के साथ मजबूती से बढ़ाये कदम

“सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।”

● स्वामी विवेकानंद

विज्ञापन के लिए : 93145 05000

जयपुर से प्रकाशित एवं प्रसारित

अजमेर, सीकर, झुंझुं, सर्वाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, हिडौल, भरतपुर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर से प्रसारित

पेज @ 3 मुख्यमंत्री मजलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित...

पेज @ 4 कांग्रेसी खुद लड़ते हैं समाज को लड़ते हैं: मदन राठौड़...

पेज @ 8 » सभी टोल्स पर फास्टैग चालू करें, रेट बोर्ड लगायें: उपमुख्यमंत्री...

न्यू अपडेट

यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मिली मंजूरी, अमद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर होगी रोक

लखनऊ/एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अमद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सक्साइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है। योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नीति लेकर आई है।

जिन्ना की तरह ही समाज को बांटने का कार्य कर रही है कांग्रेस-सपा - सीएम योगी

अलीगढ़/एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वह अंतिम समय में घुट-घुट कर मरे थे। समाज को बांटकर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला को संबोधित किया। साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब विपक्ष के लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ समूचा विपक्ष समाज में जाति का विष घोल कर अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है।

यूएस से हुई बड़ी डील, 73 हजार घातक बंदूकें खरीद रहा है भारत, दुश्मन करेंगे त्राहिमास



नई दिल्ली/एजेंसी। भारत ने अमेरिका के साथ 73,000 अरॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए एक बड़ा समझौता किया है। यह डील पहले खरीदी गई 72,400 राइफल्स के जखीरों में जोड़ी जाएगी। इन राइफल्स में 716 मॉडल शामिल हैं, जो 7.62-51 कैलिबर की होती हैं और 500 मीटर की मारक क्षमता रखती हैं। इस डील की कुल लागत 837 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। यह खरीद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली काउंसिल द्वारा दिसंबर 2023 में अनुमोदित की गई थी। यह निर्णय चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच लिया गया है। पिछले साल भारत ने अमेरिका से 72,400 राइफल्स खरीदी थीं, जिनमें से 66,400 थल सेना, 4,000 वायुसेना, और 2,000 नौसेना को वितरित की गई थीं। यह डील 647 करोड़ रुपये में हुई थी। इसके अलावा, भारतीय सेना 40,949 लाइट मशीन गन्स भी खरीद रही है, जिसमें अनुमानित खर्च 2,165 करोड़ रुपये होगा। 203 राइफल्स के उत्पादन में देरी के कारण भारत को 716 राइफल्स का आयात करना पड़ा। -203 राइफल्स, जिनकी रेंज 300 मीटर है, इस साल पहली बार 35,000 की संख्या में सेना को मिली थीं। इन राइफल्स का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो रहा है, जहां 10 सालों में 6 लाख च-203 राइफल्स तैयार की जानी हैं। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2018 में किया गया था, लेकिन विभिन्न समस्याओं के कारण इसमें विलंब हुआ है।

महिलाओं और युवाओं को सम्मान देने में सर्वोपरि रही प्रधानमंत्री जनधन योजना : पीएम मोदी

नई दिल्ली/एजेंसी।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुभारंभ के 10 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की 10वीं वर्षगांठ पूरे होने पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर किया और लाभार्थियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं। जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए। सभी लाभार्थियों को बधाई और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को बधाई। जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है।

इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए 53.13 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। इनमें 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।

सीतारमण ने कहा, हमारा लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान तीन करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते खोलना है।



उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। मार्च 2015 में प्रति खाते में औसत बैंक बैलेंस 1,065 रुपये था, जो अब बढ़कर 4,352 रुपये हो गया है। करीब 80 फीसदी खाते सक्रिय हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 66.6 फीसदी जनधन खाते खोले गए हैं, इनमें से 29.56 करोड़ (55.6 फीसद) महिला खाताधारकों के हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, चंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही है। इसके साथ साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कैम का भी फायदा सीधे लाभार्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है।

गुजरात में बाढ़ की स्थिति पर पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, मदद का दिया भरोसा



गांधीनगर/एजेंसी। गुजरात में भारी बारिश के बाद पूरे प्रदेश में हुए जलभराव की वजह से हालात अस्त-व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की और राज्य में बाढ़ के हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारी बारिश की स्थिति के संबंध में मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की और राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नागरिकों के जीवन और पशुधन की सुरक्षा पर मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही, गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

देश में 12 नए औद्योगिक शहर बनेंगे, 10 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां मोदी कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर

नई दिल्ली/एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, और बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके माध्यम से 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों में 12

नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है। इस पर कुल 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह प्रोजेक्ट 9 राज्यों में फैले 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है, जिसे देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित शहरों में स्थित होंगे: पंजाब: राजपुरा-पटियाला महाराष्ट्र: खुरगिया उत्तराखंड: खुरगिया केरल: पलक्कड़ उत्तर प्रदेश: आगरा और प्रयागराज बिहार: गया

तेलंगाणा: जहीराबाद आंध्र प्रदेश: ओरवाकल और कोयर्थी राजस्थान: जोधपुर-पाली निजी एफ एम रेडियों के 734 चैनलों की नीलामी को मंजूरी सरकार ने अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से मातृ भाषा में कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 234 शहरों में 730 निजी एफ एम चैनलों के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह मंजूरी निजी एफएम रेडियों के तीसरे चरण की नीति के तहत दी गयी है। इस चरण में 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आर्क्षित मूल्य की अधिकतम ई-नीलामी का संचालन करने का प्रस्ताव है।













